

## **EDITORIAL**

# **VRS – 2019 and Revival of BSNL**

The VRS Scheme 2019 came in to existence after approval of Union Cabinet on 23-10-2019. The Cabinet not only approved the VRS but a complete plan for revival of BSNL was also approved. Neither BSNL management nor the Administrative Ministry (DOT) discussed any of the issue with stake holder of BSNL. The BSNL employees come to know about the schemes as well as the revival plan through a press brief given by Hon'ble Minister of communication on 23-10-2019 evening. It was told that the VRS Scheme is very liberal and attractive for the employees. It is purely optional.

All the employees are free to decide to opt for VRS, but the ground level situation was not like that. The panic and fear was created upto large extent. The higher level officers threatened the employees and made the entire environment polluted. The window for option was opened on 4-11-2019 and within a week huge number of employees opted for VRS.

Compulsion was created by the officers of top level. They arranged meetings at several places to explain the guideline and what will be gain to the employee who opt for VRS, but it was learnt that the officers deputed for those meetings created panic and mounted pressure upon the employees to go on VRS. A peculiar scene was planned in entire BSNL and the employees stood in que to opt for VRS. An ugly scene was added in the history of Telecom service after a long journey of about 200 years, the Telecom sector was brought at this place where every citizen can use the modern services of Telecom. This is only outcome of the hard labour and devotion of the employees right from the beginning of magneto – system of Telephony. This sector was run by the P&T department, DoT and from 1st October 2000. The BSNL was formed in name of implementation of Telecom Policy 1999 and to provide level playing field to private operators. At the time of corporatisation the Govt. committed the job security, govt. pension to employees under Rule 37A of pension rule 1972, and financial viability of the company. Providing VRS the govt. totally deviated from its commitment of job security of the employees. According to cabinet decision of 29-9-2000, the govt. is responsible to keep this company financially viable but the govt. never took care for it rather the private Telecoms were given various concessions even to sale the product on predating price.

Now the Chapter has been changed and 78569 employees including all categories were opted for VRS. The scheme will be finalised upto 31st January 2020 and from 1st February the entire optees will be retired from service.

A big vacuum will be created after retirement of such a big number of staff but what BSNL management is going to adopt to run the services. It is again not being shared or discussed with the unions/ associations. The management has indicated that through outsourcing method company will run but the arrangement for country wide out sourced employees is not so easy. The further road map and task should be prepared upto 31st January 2020, but the BSNL management is please to complete the VRS scheme only.

The VRS and reduction in staff strength is not a solution. We have seen in MTNL where VRS was implemented twice but the company was not in a position to earn the revenue to pay the salary of staff. Again third time VRS 2019 is implemented in MTNL. By seeing the experience of MTNL it is crystal clear that only VRS will not revive the company and for that the other issues of revival plan like 4G spectrum, Land monetisation, and sovereign bonds may be taken on top priority and a time bound methodology must be started to achieve all the targets.

The management should share and discuss the restructuring and revival issues with Unions/ Associations to create a cordial atmosphere to control the situation after a huge – retirement of staff from 1st Feb. 2020.

## वी.आर.एस. 2019 एवं बी.एस.एन.एल का पुनरुत्थान

दिनांक 23.10.2019 को केन्द्रीय मंत्रीपरिषद के अनुमोदन से वी.आर.एस. 2019 लागू हुआ। मंत्रीपरिषद ने केवल वी.आर.एस. ही नहीं अपितु एक पूर्ण पुनरुत्थान योजना का अनुमोदन किया। यूनियन एवं एसोसिएशन से बिना विमर्श के जो किया गया उसकी जानकारी दिनांक 23.10.2019 की संध्या माननीय दूरसंचार मंत्री द्वारा किये गये प्रेस सम्बोधन से ज्ञात हुआ। उन्होंने बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला। बताया गया कि वीआरएस पूर्ण उदार है तथा पूर्णतः स्वैच्छिक है, परन्तु जमीनी हकीकत कुछ और हुई। उच्च प्रबंधन के अधिकारी जगह-जगह पर कर्मचारियों को वीआरएस की बारिकियों को बताने के नाम पर भयग्रस्त किया तथा वातावरण बनाया, फलतः वीआरएस आप्सन की खिड़की 4 नवम्बर से महज एक सप्ताह के अंदर प्रत्याशित संख्या में कर्मचारियों ने ऑप्शन दे दिया। ऐसा वातावरण बनाया गया कि कर्मचारी बाध्यता में आकर वीआरएस आप्ट कर दिये। कर्मचारियों पर ऐसा दबाव बनाया गया; कि वे कतारबद्ध वीआरएस आप्ट करते देखे गये। यह एक कड़वा सत्य है कि एक कुरूप परिदृश्य पैदा किया गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर्मचारियों को आतंकित करने के लिए किया गया। घर में बैठे कुछ अति बुद्धिमान प्राणी इस प्रकार का वातावरण बनाये मानो वी.आर.एस पर नहीं जाने से प्रत्यक्ष होने वाला है। भारी संख्या में साथी स्वेच्छा से नहीं अपितु घबराहट में वी.आर.एस. आप्ट किये हैं।

दूरसंचार सेवार्यें लगभग 200 वर्षों की लम्बी दौड़ के उपरान्त इस हालत में पहुंची है कि आज देश का हर नागरिक अत्याधुनिक तकनीक युक्त दूरसंचार सेवा का इस्तेमाल कर सकता है। यह ऐसे ही नहीं हुआ मैगनेटो टेलीफोन सिस्टम से लेकर आज तक डाक-तार विभाग, डी.ओ.टी.ओ और अन्ततः 1.10.2000 से बी.एस.एन.एल के कर्मचारियों के त्याग बलिदान एवं कठोर श्रम का फलाफल है। दूरसंचार विभाग को वर्ष 1999 की दूरसंचार नीति को त्वरित सफलता एवं समान प्रतिस्पर्धा के लिए, बीएसएनएल बनाया गया। दि. 1.10.2000 को बीएसएनएल के स्थापना के समय तत्कालीन सरकार ने मंत्रीपरिषद के अनुमोदन से कर्मचारियों एवं कम्पनी की आर्थिक जीवंतता की गारंटी दी थी। कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी थी और आज कर्मचारियों को भयग्रस्त करके तथा दबाव बनाकर वी.आर.एस. द्वारा सेवानिवृत्त हो जाने को मजबूर किया गया।

अभी इतिहास बदल गया है। कुल 78569 कर्मचारियों ने वी.आर.एस आप्ट कर दिया है। इनका निर्णय 31 जनवरी 2020 तक किया जायेगा। एक फरवरी 2020 को पूरे संख्या के आधे से कुछ अधिक कर्मचारी अलविदा कह जायेंगे। उनकी सामूहिक सेवानिवृत्ति होगी और एक बहुत बड़ी शून्य कम्पनी में कायम होगी। अभी तक प्रबंधन के तरफ से आगे का क्या तौर-तरीका होगा, बताया नहीं जा रहा है। दबी जबान से आउटसोर्सिंग की बात की जा रही है। पूरे देश में बीएसएनएल के लिए आउटसोर्सिंग से श्रमिक एकाएक जुटा पाना आसान नहीं होगा। प्रबंधन को आगे की रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए। वी.आर.एस. पर जाने वाली की भारी संख्या देखकर प्रबंधन बहुत संतुष्ट है पर वी.आर.एस द्वारा कर्मचारियों की संख्या कम हो जाने से कम्पनी की तरक्की नहीं हो जायेगी।

एमटीएनएल में अभी तीसरी बार वी.आर.एस. 2019 लागू किया गया है। पूर्व में दोबारा वीआरएस देने के बावजूद एमटीएनएल का राजस्व घटते गया और वेतन के लाले पड़ गये। कहीं बीएसएनएल में भी ऐसा ही तो नहीं होने जा रहा है। ऐसा सोचने के लिए बाध्यता है कि रिवाइवल प्लान के सिर्फ एक बिंदु वीआरएस पर ही पूर्ण प्रबंधन केन्द्रित है।

वी.आर.एस. की आंधी, तूफान बन कर निकल गयी अब आगे बचे हुए फौज के साथ प्लान के अन्य बिंदुओं पर कैसे अमल करना है, इसकी ठोस योजना बनानी चाहिए तथा यूनियन और एसोसिएशन के साथ वार्ता के द्वारा पुर्नगठन और पुनरुत्थान की दशा और दिशा तय करना प्रबंधन की फौरी जवाबदेही है।